हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 23–04–2012 को जन–सुनवाई खुला मैदान, नजदीक सरस्वती विद्या मन्दिर, औहर , जिला बिलासपुर हि0 प्र0 में एन0 एच0 21 के बिलासपुर से नेरचौक तक के सडक खण्ड के 4 लेन पुनरोद्धार एवं उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतू आयोजित जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरणः

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 23–04–2012 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जन–सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर की अध्यक्षता में किया गया। इस जन–सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। सर्वप्रथम हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिलासपुर द्वारा आयोजित जन–सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमुह को अवगत कराया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई की कार्यवाही शुरु की गई। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार के सदस्यों द्वारा परियोजना के प्रारुप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया ।

इसके तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई आरंभ की गई। इस जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	लोगों द्वारा उठाये गये सवाल	मुददों पर टिप्पणी
I.	**श्री बली राम निवासी गांव रिशिकेष कोठी जिला बिलासपुर–** मैं रिशिकेश कोठी, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूं । मेरे पास कुछ बीघे जमीन है और 10–15 जीव घर में रोटी खाने वाले हैं । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी जमीन के बीच सडक नहीं आनी चाहिए ।	**परियोजना निर्देशक श्री सतीश कौल जी–** इसका भुमि अधिग्रहण से कोई लिंक नही है। हमनें जो जन–सुनवाई बुलाई है। वह प्रदूषण के लिए बुलाई है। जो भी भूमि से सम्बधित एतराज होंगें उसका 3(A) नोटीफिकेशन होगा, और प्रौपर अखबार में आयेगा। जो भूमि अधिग्रहण से संम्बधित समस्यायें/ आवजैक्सन आयेगें उनका निपटारा हमारे एल0 ऐ0 ओ0 द्वारा किया जायेगा। जिसका दफ्तर, बिलासपुर जिले में खोला गया है। जिन लोगों की जो समस्यायें होगी वह हमारे

		एल0 ऐ0 ओ0 श्री बी0 डी0 शर्मा जी देखेंगे और उसका निपटारा वही करेंगे।
2.	**श्री राज कुमार , प्रधान, बहना जटटा, जिला बिलासपुर :** जैसा आपनें बताया कि यह जो जन सुनवाई रखी है, यह प्रदूषण के बारे में रखी गई है लेकिन आम जनता को इसके बारे में नही बताया गया था। हमें तो यही बताया गया था कि यहॉ पर तो जमीन के रेट तय किए जाएंगें । पहले आम जनता को बताया नही गया, लेकिन आज जो रेट तय किय जायेंगें। अभी तो हमारें साथ शुरु से ही धोखा हुआ है। पहले उजडे है फिर से उजडनें जा रहें है। शुरु से धोखा हो रहा है तो आगे क्या होगा? या तो आप लोगों के सामनें स्पष्टीकरण रखें या अपनें अधिकारियों को पहले से बता के भेजें।	**परियोजना निर्देशक श्री कौल जी–** जितनी भी पंचायतें इस सड़क के नजदीक आती है उन सभी पंचायतों को पर्यावरण की रिपोर्ट दी गई थी, और इसकी कॉपी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जिलाधीश व अन्य अधिकारियों के कार्यलयों में इसकी प्रति भेजी गई थी । हमने बताया था कि जो सभा यहॉ पर होनें वाली है। वह पर्यावरण के उपर होगी।
3.	**श्री देश राज शर्मा, प्रधान , औहर :–** यह मीटिंग प्रदूषण के लिए बुलाई गई थी। कल ही कम्पनी वालों के साथ संम्पर्क हुआ था कि यहॉ पर ऐसा कार्यक्रम होगा। लेकिन ऐसा नही बताया गया कि किस विषय पर मिटिंग हो रही है उसमें लोगों कि समस्यायें सुनी जायेगी या आपतियां भी। आपनें अपनी पंचायत के प्रतिनिधियों को भी बताया कि जो सडक यहॉ से निकलेगा उससे संम्बधित जो आपतियां होगी उन्हें दर्ज करवायें। कल पेपर में भी आया था कि लोगों कि जन–समस्यायें सुनी जायेगी लेकिन कौन सी समस्यायें सुनी जायेंगी लोगों को मालूम ही नहीं था। कि उनकी जमीन जायेगी, उसके रेट तय किय जायें, लोगों को अभी भी पता नहीं है कि रोड कहॉ से जायेगी। लोगों को अपनी जमीन के बारे में ही पता नहीं है कि उनकी जमीन जा रही है, या नही। दूसरी ओर जो हमारा पुराना रोड है उसका क्या	**परियोजना निर्देशक श्री सतीस कौल :–** प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा आज से एक महीना पहले हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था कि यह पर्यावरण से सम्बधित है। अभी कल ही अखवार में छापी गई है। और समाचार की हमें कोई जानकारी नहीं हैं। कितनी जमीन जाएगी किस खसरा नम्बर से जायेंगी। आपनें बडी अच्छी बात बताई, कि रोड में कितनी जमीन जायेगी। किस खसरा न0 से जा रही है।क्या रोड स्थापित होनें से समस्या का समाधान हो पायेगा। एक अधिसुचना 3 (A) आयेगी और उसमें पुरे कॉलम दिये

	होगा। जगह–जगह से डैमेज होगा, एन0 एच0 की विडथ (width) क्या होगी रोड की उंच्चाई कितनी होगी। जिस किसान की 10 बिघे जमीन है मान लो उसकी जमीन के दो हिस्से हो जाते है एक रोड के पार, तो एक रोड के आर, तो वह दूसरे हिस्से पर सिंचाई कैसे करेगा। हमे किस आधार पर क्षतिपुर्ति दी जायेगी लेकिन किसी को भी पता नही था कि यह मिटिंग केवल प्रदूषण से सम्बधित है।	होंगे कि कौन सी तहसील, गॉव उसमें कितना खसरा न0 दूरी हमें प्राप्त करनी है। जिस दिन अखवार में छपेगा उससे 21 दिनों के अन्दर आपकी आपतियां ली जायेंगी। तथा एल0 ए0 ओ0 आफिस बिलासपुर में जाकर कभी भी आपति दर्ज की जा सकती है।
	1962 से लेकर जो लोग डिसपलेश (Displace) हुए है आज तक वह रिसैटल Resettle) नही हो पायें है। न तो आज तक सरकार ने उन्हें जो सुख सुविधायें दी थी, वह मुहैया नही करबाई । भाखड़ा से संम्बधित जो लोग है इसके साथ–साथ पहले तो यह होना चाहिए था कि जो लोग पहले डिस्पलेश थे उन्हें दोवारा से डिस्पलेश किया जा रहा है, उन्हे सिस्टेमैटिक ढ़ग से जमीन के बदले जमीन दी जायें। और जिस तरह से सर्वे शुरू हुआ किसी भी किसान का ध्यान नहीं रखा गया और किसी भी किसान को नहीं पूछा गया। और आप सर्वे करते चले गये, और निशान लगाते गये। लोगो को यह मालूम नहीं था कि किसके मकान जा रहे है। उनको तो पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग बन रहा है या एक्सप्रैस उच्च मार्ग बन रहा है। जब यह रोड़ बन जायेगा तब हमारी जमीन जो रोड के दुसरे किनारें होगी उस पर सिंचाई कैसे होगी। क्योकि कल जब भी कोई निर्माण करना चाहेगा भी तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग से परमिशन लेते–लेते सारी उम्र कट जायेगी। एक तो डिस्पलेश होगा, उपर से कार्यालय के चक्कर काटता रह जायेगा। नियम ही कुछ ऐसे है कि उन्हें ही कोई परमिशन लेनी हेाती है जो उनके हाथ ही खडे हो जातें है, तो आम जनता का क्या होगा? हम रोड का विरोध नही करते, रोड निकलना चाहिए। लकिन रोड निकलनें के	

	साथ–साथ जो किसानों की समस्यायें है उन्हें हल करना चाहिए। और जैसे प्रदूषण, रिसैटलमैंट, और अस्पताल से सम्बधित है क्या –क्या सुख सुविधायें दी जायें यह सब आनी चाहिए।लोगो को एक रोष यह भी था जब सर्वे हुआ था तो उस समय अफरा–तफरी मची थी कि जो आज सर्वे हुआ था इस बारें में किसी को मालूम नही था कि प्रदूषण से सम्बधित मिटिंग है। प्रदूषण जो सकैंडरी है पहले तो प्राईमरी किसानों की जमीन जा रही है। घरों से डिस्पलेश हो रहे है, उनकी है।	
4	**<u>श्री अमित शर्मा, ग्राम राहियां :–</u>** मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि जिस किसान की पूरी की पूरी जमीन, घर मकान चले जायेगें, जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा उसका पर्यावरण/प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है । उसके लिए पर्यावरण कोई अहमीयत नहीं रखता है । उसके लिए तो पहले उसका घर–बार ही सब कुछ है। बदले में उस ब्यक्ति को उतनी ही जमीन दी जाए, और मकान बनाकर भी दिया जाए । आज जो यहां पर सभा होगी उसी के बारे में होगी। पर्यावरण पर हमें कोई बात नहीं करनी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो लेना देना है वह संम्पति / जमीन से लेना देना है। उसके लिए आपका और हमारा प्रदूषण कोई अहमियत नहीं रखता।	**<u>परियोजना निर्देशक श्री कौल जी–</u>** हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमानुसार मुआवजा आदि दिया जायेगा।
5	**<u>श्री राम प्रकाश, ग्रम पंचायत नौणी – मण्डी भराडी, गॉव से सम्बधित हूॅं और पूर्व में जिला परिषद का सदस्य था:</u>** – माननीय ए0 डी0 एम0 साहब, कौल जी, उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग भाइयों तथा वहनों, आज यहां पर जो मीटिंग रखी गई है, हमें यह नहीं बताया गया है कि पर्यावरण की मीटिंग है सिर्फ यह बताया गया कि औहर में एक मिटिंग है। इसलिए हमारे जो यह गरीब किसान है उनकी आज तक भाखडा विस्थापितों की समस्यायें हल	

	नहीं हो पाई है तो लोगों को यह डर है कि आने वाले समय में जो यहां पर प्रोजैक्ट का काम शुरू होने जा रहा है । उनके साथ फिर से धोखा होनें जा रहा हैं। हालॉकि हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु मैं ए0 डी0 एम0 साहब आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि आज जो सर्वे हो रहा है यहां पर जो बूर्जे स्थापित किए जा रहे है नौणी से लेकर भसड़ी तक जो ऐसा रोड है जहॉ से तीन जगह के लिए रोड निकाला जा रहा है एक तो वहॉ पर गोंविन्दसागर के उपर पुल पडने जा रहा है और एक गम्भरोला के लिए और एक जगह जो रोड वहां पर पुल पडनें जा रहा है और वहॉ पर एक ऐसा चौक बनने जा रही है और सारे रोड वहॉ पर इक्कट्ठे होने जा रहे है। परन्तु आज उसी लाइन में 5–6 परिवार ऐसे हैं कि बुर्जे उनके मकान के साथ लगाई जा रही है । और मकान के जो भी सटर है वह उच्च्व मार्ग की तरफ खुलेंगें। इसका ध्यान रखा जायें। आनें वाले समय में जो यहां पर स्कूल, पेयजल सुविधाएं उन्हे रिस्टोर (Restore) किया जाना चाहिए। जहां तक लोगों की क्षतिपुर्ति का सवाल है उसके रेट डी0 सी0 साहब ने पहले ही फिक्स किए हुए है । चार पॉच साल पहले भी रजिस्ट्रीयॉ बनी थी जो कि 18–20 लाख की बनी थी। परन्तु चार–पॉच साल बाद जमीन के बिकनें के कारण जो जमीन यहॉ बेची जा रही है। लोगो की सवसे पहले जो जमीन व मकान है उसके बारे में देखा जाना चाहिए। पहले जहॉ भी जो मुसिबत है उसे देखा जायें जो निर्णय लें इससे आने बाले समय में हम स्वागत करते है कि राष्ट्रीय उच्च्व मार्ग बनना चाहिए। पर लोगों की समस्याओं को नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिए।	
6	**श्री प्रीतम सिंह , गांम पचायत, बकरोआ , जिला**	**परियोजना निर्देशक श्री कौल जी–**

	बिलासपुर : –मैं यहां पर उपस्थित अधिकारीगण और यहां पर आए हुए सभी इस प्रौजेक्ट से सम्बधित और जो भी प्रभावित है आप सभी का स्वागत है। आपनें कहा की पर्यावरण से संम्बधित ही बात करें और अपनी समस्यायें रखें । मेरे पूर्व जितनें भी वक्ताओं ने अपनी समस्याओं को यहॉ पर रखा है मैं उनका समर्थन करता हुँ और साथ में अपनें पर्यावरण की बात कही है आपनें जो भी कितावें पढ़ी आप यहॉ पर जो भी पैरामिटर के हिसाव से काम करेगें। कितावों में आपने बहुत अच्छा लिखा है कि आप इस पर खरा उतरेंगें भी या नही यें बाद की बातें है। पर्यावरण हो या वातावरण हो, दोनों खराब होते है आपनें कहा हम सब ध्यान रखेगें। मान्यवर में कहना चाहता हुँ कि इसके उपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मै ए0 डी0 एम0 से निवेदन करना चाहुंगा कि एक ऐसी पब्लिक कमेटी बनाई जाये जो लोगों का ध्यान भी रखें और सरकार का भी। जिसमें जनता, राज्य सरकार के लोग शमिल हो राष्ट्रीय उच्च मार्ग और प्रदूषण विभाग के लोग शामिल हो, मान्यवर जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उसमें एक तारकोल मिक्सिंग प्लॉट को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है जो मापदण्ड आपनें फिक्स किये हैं वह बहुत अच्छे लिखें है। लेकिन जब वो लोग पंलाट चलातें है तो चारों तरफ धुंआ ही धुआं होता है। बजरी रोड पर फैंकी गई है और वहॉ पर तीन–चार दुर्घटनाएं हो चुकी है और उसमें 2 मौतें हो चुकी है। सरकार को कहा गया तो उसनें कहा प्रशासन को कहा गया है। लकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुझे इस चीज का विश्वास ही नही होता की पर्यावरण विभाग एक शिकायत आने पर कार्रवाही क्यों नही करता ऐसा लगता है कि वह अपनी जेब को ही देखता है और कमाई को ही देखता है। से लोग सरकार	आपके सुझाव बहुत मुल्यावान है तथा हम पैरामीटर के अनुसार ही कार्य करेगें। एक पब्लिक कमेटी भी आपके सुझाव के अनुसार गठित की जायेगी।

	की कितनी मद्द करतें है मैं निवेदन करुंगा प्रशासन से कि पंचायतें, प्रधान सरकार की कितनी मदद करते है, यहा पर जो कम्पनी आयेगी उसकी भी मदद करेंगें। और आप सभी इन बातो का घ्यान जरुर रखें। हम ज्यादातर समस्याओं का सहयोग से सुलझानें का प्रयास करेंगें। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाये पर्यावरण का ध्यान रखें दुसरी बात जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनेगा उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पडनें बाला है हमारें नदी–नाले और कुँए, उन सब पर प्रभाव पडेगा। अगर कमेटी बनेगी तो वह सब की ग्रीवेन्सीज (Grievances)देखेगी। उनकी बातें सुनेगी और प्रावधान करेगी।	
7	**श्री विजय चन्द ,गांव धराडसाणी, डमली पंचायत–** आदरणीय ए0 डी0 एम0 साहब, उपस्थित अधिकारी वर्ग और समस्त जनसमूह, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा कि जब हवाई जहाज को उड़ाना हो तो उस समय उद्घाटन के लिए हमें बुला देतें है। क्या एयरपोर्ट बन रहा होता है तो नही बुलाना पडता। जब आपनें एन0 एच0 बनाना शुरु किया तो आपनें किसी से कोई चर्चा नही की। आज प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की बात आ रही है मुझे पता तक नहीं कि कहां से क्या हो रहा है । कृप्या आप सब लोग बुद्विजीवी हैं क्या इससे पहले वह डिक्लेरेशन नही आना चाहिए था कि उसके बाद यह चीज रखी जाती तो अच्छा होता । प्रदूषण के बारे में आपने समाचार पत्र मे जो कहा था कि राजपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में छपवाया गया था कितनें लोग हमारें गॉव में पढे लिखें है जो अंगेजी का पेपर पढ सकें। हमारे गांवों में जो रोजाना अखबार पढते हैं । क्या आप एक अनाउसमैंट नही करवा सकते थे । पता नही पेपरो में ही हुई होगी आम लोगों ने	**परियोजना निर्देशक श्री कौल जी–** यह स्टेट सुपोर्ट ऐगरीमैंट (State Support Agreement) से ही बन रहा है। हम अपनी मनमानी से ये काम नही कर रहे है। पब्लिक से भी परामर्श किया गया था। यह डमली पंचायत के प्रधान से बातचीत हो रहा है। डमली के प्रधान से परामर्श करके बताया गया था कि यहां से राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाया जा रहा है। और कुछ अन्य प्रधानों से, लोगों से भी परामर्श किया गया था।

	नही सुनी होगी। लेकिन उसके उपरान्त आप एक जीप दौडा देतें तो उससे 10 प्रतिशत खर्चा कम होता। और इससे ज्यादा जनसमुह होता और तो सारी बातें समाप्त हो जाती। बाकी बातें तो पहले वालों ने बहुत अच्छी तरह से कह दी है । इस सारे कार्य के लिए सबसे पहले एक कमैटी बनाईए जो आप लोगों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही जरूरी होगी जिससे आप भी टच में रहेगे और हम भी ।	
8	**श्री जितेन्द्र चन्देल, पूर्व जिला परिषद, गांव बलोह, जिला बिलासपुर –** आदरणीय ए0 डी0 एम0 साहब, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के परियोजना निर्देशक श्री कौल जी और यहां मौजूद सभी अधिकारी व फोर लेन से प्रभावित होने वाली सम्बधित जनता, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत करता हूं और यह बडी अच्छी बात है कि यह फोर लेन हमारे इस क्षेत्र से होकर जा रही है लेकिन जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बिलासपुर की जनता पहले भाखडा विस्थापन, एन0 टी0 पी0 सी कोलडैम, ए0 सी0 सी0 वालो ने रुलाया है। अब एन0 एच वाले आये है। लेकिन जो फोर लेन हमारी जगह से होकर जा रहा है उसमें बिलासपुर जिले की 1500 विघे जमीन जायेगी उसमे कितनी सरकारी/ प्राईवेट जमीन होगी उसका क्या ऑकडा होगा। आप का जो आज का कार्यक्रम है वह प्रदूषण से संम्बधित हैं। ये तो ठीक है कि प्रदूषण से संम्बधित है लेकिन प्रदूषण की बात तो बाद की बात है मेरा ए0 डी0 एम0 से निवेदन रहेगा कि जिसकी जमीन यहां से जायेगी। सबसे पहले उन्हें विस्थापित घोषित किया जायें, और रिसैटलमैंट किया जायें। हमारे पास बहुत सारी सरकारी भुमि यहां पर खाली पडी है। मेंरा आप से निवेदन रहेगा कि उनको सबसे पहले उस जगह पर	**परियोजना निर्देशक श्री कौल जी–** यह बहुत ही अच्छा सुझाव है, यह तीन साल का प्रोजैक्ट है कम्पनी को यहां पर बीस साल और रहना है आपसे बाहर नहीं जाएगे । अभी हमने वर्क अवार्ड रिसैंटली किया हुआ है1 इसके लिए जो भी डम्पिंग साइट होगी स्वयं स्लैक्ट करेगें। एक–एक कमेटी बनेगी और डमपिंग में उसी कमेटी के तहत कार्य करेगें।

	कोलोनी बना कर दी जाये। जहां तक प्रदूषण की बात है तो कितना क्युविक मलवा यहां से निकलेगा उसके लिए डमपिंग साईट (Dumping Site) कहां–कहां बना रखे है। और कितना क्युविक मलवा यहा से निकलेगा वहॉ कितना क्युविक मलवा रखनें की कपैस्टी है। और उसमे ग्रस और प्लांटेशन (Plantation)का क्या प्रोविजन है। आपकी यहां पर भारी–भारी मशीानरी चलेगी तो जो हमारे पानी के स्त्रोत खराब हो जायेंगे। उनको बचाने के लिए आप क्या करेगें। और आपकी जो दो टनल है उसको निकालने के लिए आप इ0 वी0 एम0 मशीनरी का प्रयोग करेगें या दूसरी मशीनरी का और अगर आप दुसरा तरीका अपनायेगें तो उससे चारों तरफ प्रदूषण होगा। जो भी मकान वहां बचेगें उनकी विडीयो ग्राफी की जायें। बरमाना मे जितने भी मकान है जव वहां पर ब्लासटिंग होती है तो लोगों के घरों में दरारें आ जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसलिए काम शुरु करनें से पहलें विडियो ग्रफी जरुर करवाई जायें। प्लाटेशन के बारे में आप क्या करेंगें उसके बारे में भी बताया जायें।	
9	<u>**श्री नन्द लाल, गॉव रोहिण –**</u> सर, आप बोल रहे हैं कि दो दिन पहले जो अनांउसमैंट की गई उसमें बोला गया था कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसकी जो भी समस्या होगी वह डी0 सी0 साहब को फाइल कर सकते हैं । मेरा मकान तो पूरी तरह से रोड पर जा रहा है और साथ ही 45 मीटर की दूरी पर दूसरा मकान भी । जब मेरा मकान ही नही रहेगा तो मुझे प्रदूषण से क्या लेना देना ।	<u>**परियोजना निर्देशक श्री कौल जी–**</u> उसे पुरी तरह कम्पनसेट (Compensate) किया जायेगा। जिनका भी मकान आएगा उनको उचित मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा । एल0 ऐ0 ओ0 बिलासपुर में स्थापित किया गया है लोगों की जो भी समस्यायें होगी उन्हे एल0 ऐ0 ओ0 देखेगा। इन सभी का मुआइना करके हम इनको अवार्ड करेंगें आप अबार्ड से

		संतुष्ट नही है इसके लिए भारत सरकार ने कमिशनर नियुक्त किया है वह आपके मण्डी में है हम आपके साथ है यह काम स्टेट पॉलिसी के तहत ही बनेंगा। आपके मकान की क्षतिपुर्ति का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा। काम शुरु होने से पहले ही हम विडियों ग्राफी करेंगें। 20–25 हेक्टेयर जमीन ले रहे है जिसमें इनकी अलग से कालौनी (Colony)होगी। 2025 तक ये लोग यहां पर रहेगें और सडक मैटेंन करेगें। प्रोजैक्ट डारैक्टर यही रहेगा हम सव यही रहेगें। बाकि रही फोरेस्ट की बात इससे पहले हम फोरेस्ट की कलेरैंन्स लेगें और उसके बाद ही कार्य शुरु कर पायेगें। जो मलवा निकलेगा हम उसको उसी में डाल देंगें। डी० पी० आर० में पुरा प्रावधान है, पूरा डिटेल दिया है।
10	**श्री राम प्रकाश , पूर्व उप प्रधान औहर** – माननीय ए० डी० एम साहब मैं 60 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं, मैं पहले भी सरकार और कम्पनी के रवैये को देख चुका हूं और कम्पनी यह पहली चाल खेल रही हैं और उनकी ओर से यह पहली चाल अच्छी नहीं हैं जिला बिलासपुर से आपतियां मांगी थी हमने आपतियां दे दी है मेरे पास भी कापी है। हमारे पटवार सर्कल अमरपुर परौर में कोई एन० एच० नही है लेकिन वहां की जमीन की कीमत 35 लाख बिघा आंकी गई है और और यहां की 10 लाख बिघा आंकी	**ए० डी० एम०:–** किसी भी गॉव की 35 लाख विघा कीमत कहीं भी नही है। मै पहले भी बता चुका हुँ आप हमारे ध्यान में लाओं हम उसकी अमेंडमैंट जारी कर देगें। यह क्लैरीकल गलती हो सकती है।

	गई हैं। जो कि बहुत कम है । (how can say that)? जबकि सरकाघांट, जिला मण्डी के पास एक सडक निकली है जिसमें डी0 सी0 साहिव मण्डी ने 35 लाख प्रति बीघा मुआवजा देकर सडक निकाली है । मैं आंकडा पेश कर सकता हूँ । हमें विलासपुर के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर हमें उसी पैर्टन पर 40 से 50 लाख विघा अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो कम्पनी को रोड बनाते समय हमारी लाशो के उपर से गुजरना पडेगा ।	
11	**<u>श्री हेम राज शर्मा पंचायत वहवा जट्टा</u>**– गॉव से आया हूँ हमारे ग्रम पंचायत प्रधान श्री राज कुमार ने बताया कि औहर में एक मीटिंग है जिसके सिलसिले में हम आज यहां इकट्ठे हुए है यह एक अच्छा मौका है कि हम आज यहां इकट्ठे हुए हैं क्योकि यह तो दिल तोडने की बात नही है मै घर से एक पोईट लिख कर लाया था आप भी अपनें हाथों में पैन लेकर अपनी समस्याए लिखें। फस्ट इंप्रेसन इज दा लास्ट इंप्रेशन। अपनी अपनी समस्याएं हर बुद्विजीवी को यहां पर लानी चाहिए हमें जरूरत नहीं है कि ये लोग हमारी कमेटी बनाए हम अपनी कमेटी अपने हको की लडाई के लिए खुद बना लेगें । यहां पर मुख्य मन्त्री साहब को बुलाएगें। अगर हमको सही कीमतें और न्याय नही मिला तो हमे यहां पर आत्मदाह करना होगा। मेरे पास कुछ एक पवांईट हैं हमें मकान उसकी कैरेज समझ कर दी जाये अर्थात एक शहर की तुलना में जो मकान सडक के किनारे बने है। उनमें दोगुना से तिगुना खर्चा पडता है जो मकान सडक से 500 मीटर दूर बने है। यहां पर एक कमरा बनेगा और वहां पर तीन कमरें बनेगें। उसकी तुलना में हमें दो से तीन गुणा पेमैट मिलनी चाहिए। हमारे मकान जितने स्कुयेर फीट में बने हैं उतना ही	हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमानुसार सभी पहलुओं पर कार्रवाही की जायेंगी।

	स्कुयेयर फीट में हमें बिलासपुर या घुमारवीं शहर में उपलब्ध करवाया जाएं और शहर के सैन्टर में 5 किलोमीटर के अन्दर में ही होना चाहिए । हमें जमीन की सही कीमतें मिलनी चाहिए या फिर सरकार हमें बदले में उसी तरह की जमीन सही स्थान पर उपलब्ध करवाए । जिन भाइयों के बच्चें इन स्कूलों में पढ रहे हैं उन्हे स्पैस्ल आरक्षण दिया जायें। जिनकी पढाई डिस्टर्ब होगी। जिनके स्कूल एक तरफ से दूसरी तरफ को बदलेगें। रातों को ध्वनि का प्रकोप होगा बच्चें पढाई नही कर पायेंगे। जिन वच्चों के उपर इसका प्रभाव पडेगा या तो उन्हे स्पैस्ल आरक्षण प्रदान किया जायें। हमें और जमीन की सही कीमतें आनें के बाद हमें उसकी सही कीमतें दी जायें। और शहर में दो साल तक मुफ्त रहनें की सुविधा प्रदान की जायें ताकि हमारे बुढे माँ–बाप वहां पर रह सकें। जो व्यक्ति मकान से भी और जमीन से भी वंचित हो रहा है उनको पैट्रोल पम्प की सुविधा प्रदान की जाए । आप सभी अपनें–अपनें कुछ पंवाट लिख कर दें हो सकता चार पंवाईट मेंरे दिमाग में आयें चार आपके उन सभी पंवाईटों को मिलाकर 50–60 पंवाइट बन जायेंगें जिसमें एक लिस्ट बनेगी और हम अन्तिम सांस तक लडेंगे। भाखडा बांध की तरह नहीं होगा उसमें हमारें वुर्जुग उजडें है। हम आपके वच्चों के लिए नौकरी देगें रोजगार देंगें और आप लोगों के लिए कालोनी बनायेंगें। जैसा बिलासपुर उजडेगा हम वैसा ही बिलासपुर बना कर देगें। लेकिन हमारे बुर्जुग अनपढ थें। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा।	
12	**<u>श्री जगत राम , पूर्व प्रधान , औहर, जिला बिलासपुर</u>** :– आदरणीय ए0 डी0 एम0 साहब, कर्मचारी वर्ग व अधिकारी गण । मान्यवर 1960–61 में जब भाखडा डैम बना उस	

		समय हम लोगों को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए जैसे कि स्कूल बनेगी, रास्ते बनेगें जमीन भी गई, घर बार भी गए, हमे कुल 1200–1200 रूपया दिया और कहा कि उठाओ और चले जाओ । तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी आए हमें मिले । भजवाणी से हमारे घर आए । कालेज में जो बच्चे बिलासपुर जाते थे वह कीचड में फंसते थे, अगर नलवाडी मेले मे जाना होता था तो 22 कि0 मी0 घूम कर जाना पडता था। और अगर कोर्ट कचहरी में जाना होता था तो शिमला का किराया कम यहॉ का ज्यादा। ये मिला हमें भाखड़ा बांध से। जो हमारे यहां फोरलेन प्रोजैक्ट आ रहा है यह बहुत अच्छी बात है हम धन्यवाद करते हैं उसका भी और सरकार का भी । लेकिन किसी को उजाड़ने से पहले उसको बसाना जरूरी है। भाखडा स्कीम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है शायद अभी फैसला नहीं हुआ है । हम जानना चाहते है। कि उजाड़ने वाली सरकार, भारत सरकार और कम्पनी क्या प्रोजैक्ट लेकर आई है हम थोडा उस पर चर्चा करना चाहते हैं 1 बरमाणा में सीमेन्ट फैक्टरी कारखाना में क्या विकास हुआ सबसे ज्यादा मरीज टी0 वी0 के बरमाना फैक्टरी में ही है। और सीमींट पंजाब में 300 तो हिमाचल में 350 अगर पंजाब में 200 रु है तो हिमाचल में 225 रु ऐसा क्यों है? लोगों का ध्यान पहले रखा जाए और कम्पनी का ध्यान बाद में रखा जाए और लोगों की सेवा ठीक होनी चाहिए । क्या यह कम्पनी हमारें बच्चों को नवोदय स्कूल जैसे में प्रवेश देगें। क्या फोरटिस जैसे अस्पताल में वह हमारा उपचार करवायेंगी। अगर हमारा कोई परिवार आज उजड़ता है तो उसे बसनें के लिए 40 साल लगतें है। कमेटी व विभाग जो तय करेंगें आज से 40 साल बाद इवैल्युवेशन होगा उसके आधार पर मुआवजा हमें दिया जायें। जब कोई मैनेजर,	

	कर्मचारी निर्देशक जिला अधिकारी जब उसका 1, 1.25 लाख में गुजारा नहीं चलता, और जो हमारा किसान है, जो बची –खुची जमीन है उसमें क्या होगा। ए0 डी0 एम0 साहिव 100 विघा मेरी जमीन गई है। 10–12 विघे जो बच गई है उसके बीच से फोर लेन ले जा रहे है। किसी को कोई कन्सलट नहीं किया गया। किस तरफ से लेनी है एक तरफ से लो। बेडा गरक कर दिया है। मकानों को बचाओं मकानों की बैक साइड से जाती है तो वहां से ले जाओं हम कब इन्कार करते है। कोई प्रभावशाली नेता के चकमें आ गया, कोई किसी के चकमें में आ गया। हमारी सारी की सारी जमीन ले लो लकिन हमें 40 साल का मुआवजा दिया जायें। गरीव जनता है शाम को कमाती है और सुवह खाती है और सुवह कमाते है तो शाम को खातें है। जो लोग उजड रहे हैं, उनकी जिम्मेंवारी लें और लिखित रुप में हमें यें कॉपी दें कि ये हम आपको दें रहे है। हम 7–8 साल के थे जब भाखडा डैम बन रहा था आज हम 72 वें साल में जा रहे है लेकिन हमें आज तक कुछ नही मिला। 685 फ्लैट आज तक आपके विचाराधीन है हमें प्लौट (Plot) नहीं मिला जो वाद्वा आपनें हमारें साथ किया था वह भी आज तक विचाराधीन है। लेकिन आपनें जो प्रदूषण के बारें में आपनें कहा वह तो आपनें पहले ही बता दिया था। प्रदूषण मैने बरमानें वाला बता दिया लोग मेले को जाते है हम मेले को भी नही जातें क्योकि वहां धुल ही बहुत उडती है। प्रदूषण वालों ने कहा कि यन्त्र लगायेंगें बैसे यन्त्र यहां भी लगेगें। पहलें आशा लोगां रा ध्यान रखना बाद ते कम्पनी रा। लेकिन लोगो की ठीक सेवा करों।	
13	**श्री लाल चन्द पंडगल –** मैने जब सर्वे करनें वाले को अपना समान लेकर गांव में आते देखा तो मैने उसे पूछा	

	कि यह नई चीज आप यहां पर क्या लगा रहे है । उन्होनें कहा कि हम सर्वे कर रहे है । वे कहने लगे कि सडक आ रही है, अच्छी बात है कि सडक का सर्वे कर रहे है उन्होनें बोला यहां कहा से सवें कर रहें है इस तरफ तो पहाडी है। यहां हरिजन बस्ती है उनके पास 5–7 विस्वा जमीन पडी है। उसमें 9 परिवार रह रहे हैं। उन्होने कहा कि इन घरों से हमारा कोई कनसरन (concern) नहीं है । हम सिर्फ इस गांव का नक्शा बना रहे हैं मगर यह सडक दूसरे किनारे से जाएगी । उन्होनें नही बताया कि सडक उन्ही के मकानों के उपर से होकर जा रही हैं और उनके मकानों के पास डण्डे जैसे खडे कर दियें। और वह जो मकान है वह हरिजन बस्तीयों के जिनके पास । विघा /7 विस्वा जमीन है। उसमें से 4 परिवार वी0 पी0 एल0 परिवार है लेकिन उन्हे ये नही बताया गया कि यहां से फोर लेन जा रही है। नौणी चौक से गॉव शुरु हुआ वह पहला ही गॉव है।जब उन्होने वहां पर डण्डे गाढ़ दिये तो बोला कि यहां से फोर लेन जा रहा है। मै इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके उपर विचार किया जाए ।	
14	**श्रीमति निर्मला राजपुत गांव नौणी जिला बिलासपुर** – सर, आज जो हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं उसके उपर मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो ये फोरलेन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है लेकिन सर, जो लोग इससे उजड़ रहे हैं उनके बारे में मेरे से पहले भी बहुत अच्छे विचार आएं हैं । परन्तु खेद है कि इससे पहले भी हमारे गांव के लोग विस्थापन का दंश झेल चुके हैं । उन गांवो की हालत बदतर है वहां पर न ही सडक है, न ही पानी है, और न ही पेयजल का अच्छी तरह से प्रावधान है, और वहां के 90 प्रतिशत लोग भाखडा विस्थापित हैं । इन लोगों पर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । उनके लिए कुछ एक मांग	

	यहां पर रखना चाहती हूं । जिन लोगों की जमीने जा रही हैं उन्हे कम से कम 5–5 , 10–10 विस्वा के प्लांट दिए जाएं । उनके बच्चों को विस्थापित घोषित किया जाए और उचित शिक्षा, अच्छे स्कूल, एक जैसी प्रतिशतता के हिसाब से उनको नौकरियां देने का प्रावधान किया जाए । उनके लिए मकान और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए जिससे उनका जीवन विस्थापन होने की बजह से दूभर न हो जाए । उनकी हर मांग को ध्यान में रखते हुए पुरा किया जायें यह मांग कही पांच लाख, दो लाख और कही 10 लाख है। जिन लोगों को तो पता लग गया उन्होंने तो अपनी रजिस्ट्रीयां जल्दी–जल्दी बनवा दी लेकिन जिन लोगों को पता ही नही था वहां की कोई रजिस्ट्रीयां नही बनी है और वहां की 2 लाख वैल्यु आंकी जा रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि गरीब लोगों का ध्यान रखकर उनकी सहायता की जायें। जिनकी भी थोडी बहुत जमीन बचेगी उसका आप क्या करेंगें। इसके लिए एक कमेटी बनाई जायें और सब लोगों का घ्यान रखा जायें।	
15	**<u>श्री पी0 एल0 चौधरी , उपप्रधान ग्रम पंचायत डमली</u>** – आज की इस जन सुनवाई के अध्यक्ष अति0 उपायुक्त महोदय, एल0ए0ओ0 श्री बी0डी0शर्मा, जी, और नैशनल हाईवे अथारिटी आफ इन्डिया के अधिकारी और यहां पर उपस्थित ग्रम पंचायत से आए हुए बुजुर्गो, माताओ और बहनों, प्रदूषण के बारे में तो कुछ नही कहना चाहुंगा, यह तो सव पता हैं। लेकिन इस क्षेत्र से जब फोर लेन निकलेगा तो प्रदूषण तो इतना होगा कि जो हमारें जल स्त्रोत होगें उनपर तो असर पडेगा ही।और हमारा 2–3	

	किलो मीटर का ही ऐसा क्षेत्र है जिस पर लोगों ने आम के बगीचे लगायें है। हमारें जितनें भी आम के बगीचें है। सारे के सारे प्रदूषण से खराब हो जायेंगें। हमारी आजिविका का पूरा साधन खत्म हो जायेंगा। मेरे पास भाखडा विस्थापित के 25 परिवार आज भी ऐसे है जिनको आज तक पानी तक मुहैया नहीं करवाया गया। हमारे लिए विकास के साथ–साथ विनाश भी साथ है। मेरी डमली पंचायत में 6–7 परिवार ऐसे है जिन्होनें 50 सालों में एक प्लाट बनाया था वह भी रोड पर आ रहा है और सब लोग उजड़ रहें है। उनके पास तो टैन्ट लगानें के लिए भी जगह नही बचेगी। मैं जनता के माध्यम से अधिकारी गण के सामनें ये बात लाना चाहता हूँ कि जिन लोगो के पास जमीन नही बचेगी उनके साथ लिखित एग्रीमैंट किया जायें। मैहरोइयां में चार परिवार ऐसे है कि उनका सब कुछ उज्जड रहा है। उनकी सारी आजिविका का साधन जा रहा हैं आम का बगीचा भी जा रहा हैं। लेकिन मेरी राष्ट्रीय उच्च मार्ग वालों से प्रार्थना है कि उन्हे सब कुछ मुहैया करवाया जायें। काटा हुआ घास ज्यादा दिन नही चलता। वह समाप्त हो जाता है। जिनके पास एक विघा जमीन ही नही रहेगा उन्हे स्पैस्ल कोटे में रखा जायें और लगभग उन्हे 40 साल तक कम से कम पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य , सडंक, पानी की उचित व्यवस्था का मुफ्त प्रावधान किया जायें । और हर घर से कम से कम एक व्यक्ति को स्थाई रोजगार दिया जाए ।	
<u>**श्री दर्शन कालिया अतिरिक्त जिला उपायुक्त जिला विलासपुरः**</u> और भारतीय राष्ट्रीय उच्चमार्ग के यहां पर मौजूद प्रोजैक्ट निर्देशक श्री कौल जी और इस प्रोजैक्ट के लिए एल0 ऐ0 ओ0 श्री बी0 डी0 शर्मा जी, आज यहां आकर सही मायने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि आप लोगों के साथ शेयर किया। दो तीन चीजे मैनें देखी पहली चीज यह देखी कि आप सब लोगों की तरफ से अच्छा उतर मिला हैं सब लोगों ने यह कहा कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग बन रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि यह एक विकास का कार्य है । मैं सभी का इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं । थोडे से मेरे साथी कुछ जोश में भी थे शायद उनकी पहले कोई पीडाएं रही होगी ।		

परन्तु मैं आज आपसे कह सकता हूँ कि अभी ऐसा देखने की जरूरत नहीं हैं, हम बैठे है सुनने के लिए, प्रोजैक्ट निर्देशक ने आपको बडे ध्यानपूर्वक सुना और मैं यह कह सकता हूं कि यह जो कार्यक्रम है पब्लिक हीअरिंग प्रदूषण से संम्बधित थी। परन्तु आप लोगों ने जो दिक्कतें बताई आप लोगों ने अपने मन के विचार व्यक्त किए अच्छे हैं । जहां तक प्रदूषण की बात है मैं बेशक पहले में यहां पर उन्ही के साथ बैठा हूं परन्तु बडे क्लियर तौर पर मेरा दिल आप लोगों के साथ है । प्रदूषण पर जो आंकडे दिए गए है वह आंकडे सन्तोषजनक नहीं हैं । इस समय जो मेरे पास आंकडे हैं 1000 करोड रूपये के इस प्रोजैक्ट मे से सिर्फ 2 करोड रूपये प्रदूषण के लिए खर्चना पडें जो बहुत ज्यादा कम है। इस प्रोजैक्ट के लिए जो 1000 करोड के आकडें है उसमें से 2 करोडं रु? ये मेरी तरफ से इस प्रोजैक्ट को सलाह रहेगी। और इन आंकडों को सुधारियें । प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान किया जायें । मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि शुरू मे यहां पर कि किसकी कितनी जमीन जानी है , कौन सी किसी जमीन जा रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी पहले अधिसुचना हो जाती तो बहुत अच्छा होता । ये अधिसुचना इनकी तरफ से चली गई है वहुत जल्द ही प्रकाशित होकर आ जायेगीं। कौन सा खसरा नम्बर कौन सी जमीन से जा रहा है । जो लोग जमीन से वेघर हो रहे हैं। इन लोगों को इस एक्ट मे ज्यादा से ज्यादा राहत दी जायें। जो हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग आ रहा हैं वह अभी तक किरतपुर तक पंहुच गया है। ऐसा नही है कि एन0 एच0 पहले कभी नही बना है। जहां – जहां भी पहलें बना है एल0 ऐ0 ओ0 साहिव वहां पता जरुर करें। कि वहां पर जनता को कौन से अच्छी से अच्छी सुहलतें प्रदान की गई वह यहां पर भी मिलनी चाहिए। एन0 एच0 एक्ट के आधार पर इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए। यह सारा प्रोसैस जल्दी से जल्दी हो जाना जरूरी है । प्रदूषण के लिए जो दो करोड रूपये की राशि रखी गई है जो कि बहुत तुच्छ है, बढाई जाए । इस हाइवे प्रोजैक्ट को जनता की इच्छानुसार इस पर अमल करेगें ।

अंत में हाइवे अथारिटी आफ इन्डिया के परियोजना निर्देशक ने उपस्थित जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में सहयोग मांगा तथा क्षेत्र के विकास में यथासंम्भव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा जनता का आभार व्यक्त किया ।

अन्त में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर व सहायक अभियन्ता पर्यावरण बोर्ड बिलासपुर द्वारा लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24–04–2012 को जन–सुनवाई महाराजा लक्ष्मण सेन स्नातकोत्तर महाविघालय प्रांगण, सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 में एन0 एच0 21 के बिलासपुर से नेरचौक तक के सड़क खण्ड के 4 लेन पुनरोद्वार एवं उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतू आयोजित जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरणः

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24–04–2012 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जन–सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी, मण्डी की अध्यक्षता में सुन्दरनगर में किया गया। इस जन–सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड के प्रतिनिधि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण, बोर्ड, बिलासपुर द्वारा आयोजित जन–सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन–सुनवाई की कार्यवाही शुरु की गई। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार के सदस्यों द्वारा परियोजना के प्रारुप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया । इस जन–सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0	लोगों द्वारा उठाये गये सवाल	मुददों पर टिप्पणी
1.	**श्री जोगिन्दर वालिया, अध्यक्ष, किसान सभा, गांव भौर, डा0 कनैड, जिला मण्डी हि0 प्र0 –** मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि जो आई सी0 टी0 वालों ने जो प्रोपोजल बनाया है इसमे जो टोटल प्रोपोजल मण्डी जिला से संम्बधित है, यह 63 किलोमीटर का प्रस्तावित क्षेत्र है। इसमें जो नया क्षेत्र है वह 52 किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि 45 किलोमीटर क्षेत्र में आएगा। उसके बाद दो क्षेत्र ऐसे हैं जो जड़ोल से लेकर सुन्दरनगर तक और सुन्दरनगर से आगे धनोटु से वाईपास का प्रस्ताव है । (नौलखा से डडौर का जो 4 किलो मीटर का क्षेत्र है वह क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है जो 11 कि0 मी0 का स्पैन बचा उसमें एक रोड और है) जो की नौलखा तक जायेगा जो कि बहुत कम है। यह रोड टोटल 63 किलोमीटर ही रहना चाहिए । इसे डिस्टर्ब (Disturb) क्यों किया जा रहा है । इसमें 656 लोग प्रभावित हो रहे हैं। मेरा अनुरोघ है कि आई0	**परियोजना निर्देशक श्री सतीश कौल जी –** वैसे यह जो सड़क बनाई जा रही है यह लोगों को तंग करने के लिए नहीं बनाई जा रही है । इसे आपकी सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है । आपको पता है कि स्वारघाट में बहुत जाम लगता था जिससे आम आदमी बहुत परेशान होता था । इससे निजात दिलाने के लिए भी फोरलेन रोड बनाया जा रहा है । आपको जो भी इस फोरलेन बनने के समय तकलीफ होगी उसे हम देखेंगे और तुरन्त विचार करके उचित फैसला लेगें ।

	सी0 टी0 वाले इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से कनसीडर (consider) करे । एस0 डी0 एम0 सुन्दरनगर यहां पर बैठे है, वे भी जानते है कि इस क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा कन्ज्सन (conjestion) है और यह सबसे ज्यादा एक्सीडैंट प्रोन क्षेत्र है तथा ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और रोजाना दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं । यहां की समस्या इतनी गम्भीर है कि उसको हम इमेजिन नही कर सकते । दूसरी बात यह है कि कल को आप प्रेजिडैट ऑफ इडिया का नोटीफिकेशन लाएंगें कि यह फोरलेन बननी देश हित में है तथा देश की सुरक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है । अगर आपने यही करना है तो मैं तो कहता हूॅ कि यह रोड़ हमारी जमीनों के एक साईड से निकाला जाए । मेरा घर जो 24 मीटर एक साईड से जा रहा है और 30 मीटर वहां मेरी जगह है तो मानको के हिसाब से जो 6 विस्वा बचेगी उसका मैं क्या करूंगा । लेकिन सवाल यह है कि जब वह तोड़ेंगे तो मेरा तो पूरा घर ही टूटेगा तो उसे पहले ही पूरा ले लिया जाए । वह थोडी सी जगह भी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी । हम सरकार के खिलाफ नही है कि सडक न निकले यह रोड तो 80 कि0 मी0 रह जायेगा हमें तो चण्ड़ीगढ जाना और आसान हो जायेंगा। मेरा मानना है कि आपनें जो रोड़ लेना है वह आप चाहें 30 मी0 लो चाहें 40 मी0 लो हम इसके खिलाफ नही है। हम विकास के खिलाफ नहीं है लेकिन मेरा मानना यह है कि रोड को शहर के एक साईड से लिया जाए । इस रोड पर कन्ज्सन ही रहेगा और सारे लोग इस रोड पर ही चलेगें फिर दूसरे रोड से नहीं जाएंगें । तीसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो हमारे चार लिंक है वह 500 मीटर के दायरें पर है । कनैड से आगे चलकर डावण गांव के लिए कुनैक्टीविटी (connectivity)	

	जाती है । उसके बाद डावण को रोड़ जाता है और आगे डिस्पैन्सरी, स्कूल तथा सैरीकल्चर फार्म हैं । यह तो मैनें 500 मी0 के बारें में ही कहा लेकिन फोर लेन की गाईड लाईन है की हम 500 मी0 तक सीधा देंखेंगे। मै अगर डडोर चौक से अपनें घर को आना चाहुँगा तो कहां से आऊॅगा। कृप्या बतायें। क्या डावण जाने वाला कनैड़ से आएगा । उसके लिए जो आप 24 मीटर की बात कर रहे हैं, आप बताओ कि सर्विस रोड वहां पर कहां रहा । माननीय कौल साहब ने कहा कि 45 मीटर का सर्विस रोड होगा । उसके साथ जोडने के लिए जो आपका लिंग रोड होगा उसे कैसे प्रस्तावित करेंगें । चौथी एक सबसे जरुरी कलियरैंस आपको करनी होगी कि क्या अलग रोड बनेगा या बाई पास होगा लेकिन मान लो नहीं बनता है । अगर आपनें बना ही दिया तो 24 मीटर के दायरे में रहना एक जेल जैसा हो जाएगा मेरी पंचायत जहॉ से शुरू होती है वह है नागचला । वह फलड प्रोन (flood prone) क्षेत्र है । नेरचौक वालों को आजतक कोई क्षतिपुर्ति नहीं मिली ढढौर के उपर से पानी आता है । अगर आपने उसके निवारण के लिए कुछ नहीं किया तों रुक जायेगा । आपसे मेरा निवेदन है कि ढढौर में फलाई ओवर बनना चाहिए। यह हाईली फलड प्रोन क्षेत्र है । इसलिए उस एरिया में कोई विकास नहीं हो सकती । क्योकि हमारा औद्यौगिक क्षेत्र रती में हैं । मेरा आपसे अनुरोघ है कि इस क्षेत्र में आपको फलाई ओवर का प्रस्ताव बनाना ही पडेगा । मेरा सुझाव है माननीय सरकार से व श्री सतीश कौल, परियोजना निर्देशक जी से कि सुन्दरनगर से नेरचौक तक फलाई ओवर बनाया जाए । पंजाब में भी 8 किलामीटर का जिरकपुर से सीधा परवाणु के लिए फलाई ओवर है । क्यों न आप इस 63 किलामीटर वाले स्पैन को 52–53 किलोमीटर करें और सिर्फ 7	

	किलोमीटर को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं । क्योंकि यहां कि जनता छोटा मोटा इसी क्षेत्र में व्यापार करती है । यह क्षेत्र ऐसा है माननीय ए0 डी0 एम0 साहब यदि व्यापार नहीं होगा तो इस क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं होगा । इस रोड के आने से जब रास्ता ही नहीं बचेगा तो कौन खड़ा होगा, उसकी दुकान से सामान लेने, पता नहीं वे दुकानदार क्या करेगें? इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इस फलाई ओवर का प्रावधान अवश्य करें । इस इलाके के हकों के लिए यह किसान सभा हमेशा यहां की जनता के सहयोग के लिए खड़ी रहेगी । लेकिन अगर आप लोगों को तोडेंगे, तो हम आपको थोडा सा तोडेंगे जरूर ।	
2.	**श्री विजय अवरोल , गांव कनैड, जिला मण्डी** – सर, जैसा कि वालिया जी ने रोड़ के उपर नौलखा से लेकर डडौर तक अभी मुझसे पहले डिस्कस किया, इस पर मैं भी अपना सुझाव देना चाहता हूं । जब आप सुन्दरनगर से नौलखा बाईपास निकाल रहे हैं तो क्यों न इसको सुकेती खड्ड तक चैनलाईज किया जाए वहां से अगर आप सीधा डडौर बाईपास निकाल दें तो सारी समस्या का ही हल हो जाएगा । कोई भी तंग नहीं होगा भुमि भी आपको सस्ती मिलेगी ।	
3.	**श्री उपेन्द्र ठाकुर, ग्राम पंचायत चौक, नौलखा जिला मण्डी**– मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार का जिन्होनें इतना बडा प्रोजेक्ट हमें इस इलाके के लिए दिया है, इसमें कोई राजनिति नहीं की गई है । हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज आप यहां आये हैं । मैं धन्यावाद करना चाहता हूँ प्रशासन का तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार से आए हुए परियोजना निदेशक, श्री सतीश कौल जी का । यह	**श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक**–आज की बैठक केवल पर्यावरण सें संम्बधित थी । जहां तक भुमि अधिग्रहण का सवाल है इसका केन्द्रिय सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजा गया है । यह जैसे ही आएगा राजपत्र में जारी कर दिया जाएगा । उससे साफ पता चल जाएगा कि कौन सा गांव, कौन सी

	बात ठीक है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पडता है । लेकिन आपने पहले यह नही बताया कि एन0 एच0 आ रहा है और किन–किन लोंगों के घर टुटेगें। पहलें यह तो साफ किया जायें की कहां से ले रहें है दायें से या बायें से। जहॉ तक फलाई ओवर की बात की जा रही है, मैं बिल्कुल पूर्व वक्ता श्री जोगिन्द्र वालिया की बातों से पूरी तरह सहमत हूॅ । लेकिन हमें आई0 सी0 टी0 वालों के सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि हमारा घर 4–5 मीटर जाएगा परन्तु मेरा घर तो पूरा ही डिसमैंटल किया जाएगा । पहले तो यह बताया जाए कि कितनी जमीन कहां से ली जा रही है । पिछले दो सालों में इस रोड पर जितनी भी दुर्घटनायें हुई वह बाईक से संम्बधित सबसे ज्यादा व्यक्तियो के एक्सीडैण्ट हुए है और कम से कम 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों की मौतें हुई है। इसलिए यह रोड सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपुर्ण है। और जो आंकडे आपने मरनें वालो के बतायें वह संतोषजनक नही है। इससे कहीं ज्यादा है । इसका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है । हमें मुआवजा कितना मिलेगा प्रभावितों को मारजन मनी (margin money) कितना मिलेगा । जो जिन्दगी भर की मेहनत से हमनें अपने लिए घर तैयार किया है क्या उस पैसे से हम अगले पॉच सालों में भी घर बना पाएंगें । अगर मेरा मकान 10 कमरों का है तो क्या मैं ऐसा घर बना पाउंगा । जो सरकार ने रोड का काम शुरु किया उसके लिए हम खुश है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपुर्ण है। आप कितना पैसा हमें दे रहे है इसका भी हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए । सरकार ने जो यह फोरलेन बनाने की शुरूआत की है उससे हम बहुत खुश हैं । जहां पर यह रोड बनेगा उसके बाद सुरक्षा की दष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु पहले कम से कम हमें	तहसील और किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि हम लेने जा रहे हैं । अधिसुचना होनें के बाद 21 दिन के अन्दर एल0 ए0 ओ0 विलासपुर में जो आफिस अभी खुला है वहां जाकर अपना ऑवजेक्सन फाईल कर सकते हैं । वहां हमारे एल0 ए0 ओ0 साहब उपलब्ध रहेगें । जहां तक मकानों की बात है उसका पुर्नमुल्यॉकन लोक निमार्ण विभाग के द्वारा करबाया जायेगा । और जो भी क्षतिपुर्ति होगी हम उसका पूरा मूल्य देंगे।

	यह कलीयर (Clear) करें कि हमें सहायता क्या दी जा रही है ।	
4.	**श्री एम0 एस0 चौधरी ,गांव ढढौर, जिला मण्डी** मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि वालिया जी ने बताया कि सबसे ज्यदा नुक्सान सुन्दरनगर से डडौर तक हो रहा है । वहॉ के लोगों को कोई पता नहीं है कि हमारा घर जा रहा है या नहीं , उनको यह पता नहीं कि जमीन कितनी जा रही है । उन्हें यह बताया जाए कि आगे क्या करना है । क्योंकि यहां पर जो लोग रहते है बहुत कम जमीन उनके पास है । दूसरा प्रश्न मैं बाई पास का पूछना चाहता हूँ । डडौर से नागचला जैसा कि वालिया जी ने कहा कि यदि वहां पर रोड बनता है तो वहां पर सबसे उपजाउ भूमि खराब हो जाएगी हैं । उसका खास ख्याल रखा जाए और उस भूमि को बचाया जाए और इस क्षेत्र में फलाई ओवर बनाया जाए ताकि लोगों की जमीन वहां खराब न हों , यह मेरा आपसे अनुरोध है ।	**श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक–** जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बराबर यह अधिसुचना 3 । की बडे अखबारों में आएगी ।यह अधिसुचना अनुच्छेद 3–डी0 के अर्न्तगत होगी । इसमें सब व्यक्तियों के नाम आ जायेंगें जिनकी जमीन जा रही है। उसके बाद आपतियां ली जायेंगी और आपतियॉ प्राप्त करनें के बाद उसमें नाम व खसरा नम्बर इत्यादि सब होगा और हमें जितनी भूमि की जरूरत होगी उतनी ही ले ली जाएगी । उसी अधिसुचना के अनुसार आपको मुआवजा भी दिया जाएगा ।
5.	**श्री जोगिन्दर वालिया –भौर – मण्डी** सर, लोगों को पता चल गया है कि हमारी जमीन आ रही है जिसकी 30 मीटर आएगी उससे सिर्फ 24 मीटर ही न ली जाए क्योकि वे उस बची हुई 6 मीटर जमीन का भी कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगें । आप पब्लिक मिटींग तो करो ना। और इसके साथ लगती दुकानेंा का क्या होगा? यहां पर लोगों ने जिस दिन से यह सुना है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग आ रहा है व्यापार की दृष्टि से लोग बहुत परेशान है ।यहां भाई विजय गोयल जी है जिनकी दुकानदारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी । कनैड और भौर के बीच की दुकानों का क्या होगा । क्योकि रोड उन दुकानों से उंचा होगा और दुकानें नीचे चली जाएगी । हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी दुकानें बनाई हैं और तब जाकर वे छोटे मोटे व्यवसाय	

	कर रहे हैं । उनकी दुकानदारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी । 24 मीटर में कोई स्पेश नहीं रहेगा । गरीबों का पूरा ख्याल रखा जाए तभी आज की इस जन–सुनवाई का सही मायने में अर्थ निकलेगा ।	
6.	**<u>श्री ओ0पी0 मौदगिल, प्रधान – ग्राम पंचायत डैहर जिला मण्डी</u>** मैं इस फोरलेन का जो यहां से निकलने जा रही है, इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहां विकास होता है वहां विनाश भी होता है । कहावत कि ओर क्यों जाना है। मैं तो डैहर पंचायत के बारे में थोडे सवाल रखूंगा। जहां हमारी डैहर पंचायत में फोरलेन के कार्य के लिए जो जमीन जा रही है । वहां पर हमारा एक बहुत पुराना रोड है और अन्य गांव के बीच जाने के लिए भी छोटे छोटे रोड हैं । जब आपकी फोरलेन वहां से निकलेगी तो ऐसा न हो कि डैहर के लिए कोई स्टौपेज Stopage न हो और सीधा सुन्दरनगर बन जायें । हम चाहते हैं कि डैहर में जो रोड है उसका लिंक वहीं साथ में फोरलेन के साथ किया जाए न कि 20 किलोमीटर की दूरी पर किया जायें । जैसा कि जमीन के बारे में बात की गई कि हमारे मकान और जमीन जा रही हैं । आप सिर्फ 150 मीटर जगह का पैसा देगें । परन्तु वहां जो मकान 2 विस्वा के बीच बना था, अगर उसमें आधा विस्वा जमीन बच जायेंगी तो उसका मैं क्या करूंगा । अतः जो साथ वाली बची हुई जमीन है उसका भी विभाग को पूरा पैसा देना होगा । इस रोड के निकलने से हमारे पानी के जो स्त्रोत है वह पुरी तरह से खराब हो जायेंगें। जब रोड निकलेगा । क्योकि हमारा डैहर एरिया जो साथ में एक किलामीटर की दूरी पर जो हमारी पुरानी वावडी है कुंए हैं, उनकी	**<u>श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक–</u>** उसका पूरा प्रावधान डी0 पी0 आर0 में रखा गया है। इन सब समस्याओं का जबाब हम दे भी चुके हैं । हम झूठा वायदा नहीं करना चाहेंगे । नैशनल हाइवे की डी0 पी0 आर0 के अन्दर जो सुविधाएं देने का प्रावधान होगा वे सभी प्रभावितों को उपलब्ध अविलम्ब करवाई जाएगी ।इसमें एक एक्ट बना हुआ है हम उस एक्ट से बाहर नही जा सकतें क्योंकि यह भारत सरकार से स्वीकृत है। पैन्शन का वादा मैं नहीं कर सकता क्योकि हम एक्ट के बाहर नहीं जा सकते । इसमें नियम बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। जहां पर भी दुर्घटनायें होगी वहां पर हमारी टोल प्लाजा में ऐम्बुलैंस लगी होगी ऐसी स्थिति में आपको तुरन्त सुविधा मुहैया करवाई जायेंगी। आपका ट्रैफिक भी न रुके इसके लिए पैट्रोलिंग भी की जायेंगी। कम्पनी इसका 25 वर्षो तक देख–रेख और और रख–रखाव का पूरा ध्यान रखेगी।

	पूरी निगरानी व रखरखाव उच्च मार्ग वाले करें ताकि हमारा पानी खराब न हो। उसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए । जो कम से कम 50 साल तक नोट कमाएंगें । अभी पैसों की बात आई ही नही है । यह भारत के अखाद्य रोड चाईना के लिए निकल रहा है। 'ना विलिंग नो फिलिंग' इस बारें में हम सभी जानतें है। पैसा कमानें वाली कम्पनी पैसा कमायेंगी इसमें गरीबों को शायद ही कुछ मिले । हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, जैसा कोलडैम बनने से हुआ है, लोगों को पैसा मिला है, परन्तु आज उन लोगों के पास पैसा नही बचा है सिर्फ 10 परसैण्ट (percent) लोगों के पास पैसा बचा है, 90 परसैण्ट लोगों के पास पैसा नहीं बचा है । मेरा यह कहना है कि कम से कम जिन लोगों की जमीन जाएगी उस घर से 60 साल से उपर के बुजुर्गो को 5 हजार प्रतिमाह पैन्शन लगे । जो उनकी चल और अचल संम्पति थी वह तो रोड में चली जायेंगी पैसा तो वह कमायेंगें। एक प्वाइंट और नोट किया जाए कि डैहर के अन्दर जो पी0 एच0 सी0 है उनके लिए हाइवे की तरफ से एक ऐम्बुलैंस होनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है 'सच्चाई छुप नही सकती बनावट के उसूलों से खुशबु नही आ सकती कागज के फुलों से। 20 किलो मीटर के एरिया में जो दुर्घटनाए होती है उनके लिए मुफ्त ऐम्बुलैंस की सुविधा लोगों को होनी चाहिए। ताकि सुन्दरगर और मण्डी के लिए आपातकालीन स्थिति में रोगी को तुरन्त पहुंचाया जा सके। उनको सी0 एस0 टी0 वालो के तहत जिला अस्पताल और राज्य अस्पताल में लेकर जायें। और ज्यादा न बोलता हुआ आपका धन्यावाद करता हूँ। हमारी फरीयाद है कि हमारे पैंशन के बारें में भी कुछ किया जायें।	

7.	**श्री बेली राम गांव पंचायत डडौर, जिला मण्डी:–** जैसे आप करोडों रुपय मुआवजा इन लोगो को दे देगें उसके बाद कहेगें कि आप यहां से उठ जाओं।यदि नही उठेगें तो निकाल दिये जाओगें । ये लोग अपनी टैची लेकर कहां जायेंगे जो इनके लिए तो काला पानी हो जायेंगा। इनके लिए क्या राष्ट्रीय उच्च मार्ग वालों की तरफ से इनको रहने के लिए मकान देगी या पुर्नवास के लिए जमीन देगी। ये मेरा सवाल है। सडक के किनारे जो दुकानदार हैं वे कहा जाएंगें जब उनकी दुकाने तोड़ दी जाएगी ।	**श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक–** एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है ।
8.	**श्री हुकम चन्द, एडवोकेट, ग्राम पंचायत डडौहर, जिला मण्डी** –यह कहना चाहूंगा कि जो सुन्दरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मेरी जमीन और मकान है उसका क्या होगा । आज का जो मुख्य मुद्दा है वह यह है कि पर्यावरण से क्या हानियॉ और लाभ होने जा रहे हैं । इस मुद्दे पर लोग इधर–उधर भटक रहे है जो सरकार की बात है यह बडी कीमत की बात कि जो सरकार ऐक्वजिसन के प्राधिकारी ऐसे नही देंगें तो हम दूसरे ढंग से भी लेना जानते है लेकिन आज का जो मुद्दा है वह पर्यावरण से सम्बधित है पहले जो हमारा डैहर से होकर रोड जाता था। यें तो प्रधान जी ने पहले बोल दिया ठीक हो गया। आगे जो यह मिलेंगा यह पुल तक मिलेंगा, आगे नौलखा तक होगा। बीच का जो बाई पास (by pass) क्षेत्र है उसमें लोग कलैरटी (clarity) चाहते है कि यें बाई पास कैसे बनेगा इसका अलग से टैंडर होगा। या जब तक ये बाईपास नही बनता है तो आप इसको सडक से एक्सपैंड करेगें। हाइवे वाले क्या क्या करने जा रहे है1 क्या लोगों के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगें, क्या बाई पास की व्यवस्था होगी । क्या यह रोड नैरचौक तक जो बनेगा क्या इसका टैंडर हो	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी–** यह जो सुन्दरनगर बाई पास के बारे में आपने पूछा यह बाई पास हमारे प्रोजैक्ट से शुरू से ही प्रस्तावित था। यह रोड राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग के मुख्य अभियंता राज्य सरकार के अधीनस्थ हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 पण्डोह के अन्दर आता है इसका कार्यभार इन्ही के अण्डर दिया गया है इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सुन्दरनगर बाई पास हि0 प्र0 राज्य सरकार ही बनायेंगी दोहरा लेन यह लोग बनाएंगें और उसको बाद हमें हैडओवर करेगें । इसी को हम दो से चार लेन बनायेंगे, यह रोड तभी शुरु होगा जब यह चरण पुरा होगा। जो राज्य सरकार का रोड है वह राज्य उच्च मार्ग बनकर राज्य सरकार को आउटोमैटिक ही हैडओवर हो जायेंगा।

	चुका है, क्या यह नौलखा तक एक्सटैंड होगा और यह सुन्दरनगर का बाइपास किस तरह से बनेगा ।	
9.	**<u>श्री राम लाल , गांव देहवी ग्राम पंचायत कांगू , जिला मण्डी</u>** – मेरा आप से एक अनुरोध है कि मैने एस0 डी0 एम0 सुन्दरनगर के माध्यम से आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी के लिए जो समस्यायें भेजी थी उन्हें आर0 डी0 155 –56–57 उपजाऊ भूमि को काट दिया जा रहा है एक साईड से लो जैसे यें ग्राउड है आप बीच से नही ले जा सकते जींमीदार आदमी है दोनो तरफ से काम नही कर सकतें इसलिए जमीन एक तरफ से ले। अगर आपने जबरदस्ती की तो हम कोर्ट का दरबाजा खटखटायेगे। आपके अधिकारियों ने मुझे भी धमकाया अगर हमारी मांगे नही मानी तो हम रोड नही निकलने देंगे। इस जमीन से रोड एक साईड से निकाला जाए । कि क्या ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि जोर जबरदस्ती हमारे साथ की जाए । आप 200 मीटर लेंगें हमारी जमीन तो पूरी तरह से खराब कर देगें आप यह नोट कर लें और इसके लिए उचित उपाय कर लें	**<u>श्री परियोजना निदेशक, श्री कौल जी</u>**– इसको फिर स्टडी करेगें कि वहां क्या सम्भव है ।
10.	**<u>श्री सत्य देव प्रधान, ग्राम पंचायत जडोल, तह0 सुन्दरनगर , जिला मण्डी</u>** – माननीय ए0 डी0 एम0 साहिब ये जो राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग प्राधिकारी वाले है, यहां जडोल से लेकर पुंग तक बस रही आवादी को आवादी नहीं मानते है, यह जो 8.5 किलोमीटर रोड यहां से बन रहा है इस पर बिल्कुल विचार विमर्श नहीं हुआ । आज यहां बात हो रही है पर्यावरण के उपर । पर्यावरण की जरूरत किसको है जब इंसान ही उजड जाएगा तो इन्सान ही नहीं रहेगा तो पर्यावरण से हमारा क्या लेना देना, रोड किसके लिए बनाये जाए इंसान के लिए, जिसमें बीमार आदमी आराम से ले जा सके । अब आदमी ही बीमार करने के लिए रोड बनाया	

	जाए तब उसे कोई फायदा नहीं है । आदरणीय कौल जी ने उदाहरण दिया कि इसके बनने से स्वारघाट में जाम से निजात मिलेगी , दिल्ली चण्डीगढ जाने के लिए आसानी होगी । लेकिन मेरा जो एरिया ग्राम पचायत जडोल से शुरू होता है वहां बहुत से मेरे भाई ऐसे है जो रोजगार के लिए यहां आएं हैं । भाई रामलाल ने ठीक ही कहा जब खेत में हल चलाया जाएगा तो मिट्टी तो खुदेगी ही । मेरा सुझाव है कि एक साइड से रोड बनाया जाए, या खड्ड के किनारे से रोड बनाया जाए । कोई ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं देनी पडेगी सारी सरकारी भुमि है । अगर ऐसे ही रोड बनेगें अगर लोगों को उजाड़ना ही है तो अलग बात है । आप देखिए जडोल से लेकर सुन्दरनगर तक अच्छे अच्छे होटल है जिनकी दो दो लाख रूपये सेल है । तो इन होटल वालों ने क्या करना है और वह होटल वाले कहां जाएंगे । बाहर से यहां लोग कमाने के लिए आए हुए है । जब तक रोड क्लियर नहीं होगा राज्य सरकार या केद्रिय सरकार हम सब यही चाहते हैं कि जो दुर्घटनाएं होंगी उसका पूरा खर्च कम्पनी वहन करें । रही पानी की बात वह हो जायेंगा। हमारे यहां बी0 एस0 एल0 प्रोजैक्ट बना, पहले हमारे पानी के स्त्रोत खराब हुए वहां सिंचाई होती थी उसका पैसा आज चाहे केद्रिय सरकार ले, चाहे कम्पनीयां ले रही है लेकिन जिसका घराट बन्द हो गया उसको क्या मिला। उसका असली फायदा अभी कोल डैम प्रोजैक्ट 900 मेघावाट का बन रहा है । जिनको 50–50 लाख मिला है वह खत्म कर चुके हैं । उनके लिए बना दी विस्थापन पुर्नवास कालौनी कागूं में परन्तु उस कालोनी में कोई नहीं रह रहा है । बल्कि लोग उस जमीन पर खेतीवाडी कर रहे हैं क्योकि वह जमीन रहने के लायक है ही नहीं । मेरा मतलब है कि जडोल से लेकर पुंग तक रोड के लिए एक साईड का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि यहां के होटल व्यवसायी	

	बर्बाद न हो । हांलाकि नौलखा से लेकर ढढौर तक होटल नहीं हैं फिर भी ये लोग भयभीत हैं । यहां पर होटल लोगों ने किराए पर लिए हुए हैं । रोड तीन साल में बन जाएगा परन्तु उस व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा । क्या आप क्षतिपुर्ति देगें होटल वाले को, या नहीं देगें । सबको पता है कि पैसा कभी भी टिकता नहीं हैं । हवा, पानी और पैसा ज्यादा देर नहीं टिकता है । इसमें क्या प्रदुषण, क्या पर्यावरण, किसान आज भी आर्थिक तंगी में है। हिमाचल में इस समय आज लगभग 75 लाख आवादी है उसमें से 5 परसैण्ट लोग शहरों में रहते हैं और 95 परसैण्ट लोग गांव मे ही रहते हैं। तो कौल जी जो 95 परसैण्ट लोग गांव में रहते हैं । उन लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नही है ऐसे विकास से कोई लेना देना नहीं हैं । उन्हें तो सिर्फ अपने जमीन और मकान के बारे में चिन्ता रहती है । मेरा निवेदन है कि जडोल से लेकर पुंग तक जो 8.5 कि0 मी0 का रोड है इस रोड के बारे किसी से कोई बात नहीं की गई । ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा यह बडे दुःख की बात है । दूसरी बात जो पर्यावरण की बात है मेरे ख्याल में पानी के स्त्रोत जो खराब होगें उनको एक बार तो आप ठीक कर देगें, उसकी क्षतिपुर्ति भी मिल जाएगी परन्तु बाद में कोई उसकी सुध नही लेगा जडोल में पानी के अच्छे –अच्छे स्त्रोत हैं जिनको पूरी तरह से हाइवे वालों को सुरक्षित रखना पडेगा । जैसा चौमुखा में एक पानी का स्त्रोत हैं उसमें बिजली बनती थी, और जो जडोल का पानी था उसको तो जॉचनें के लिए जर्मनी की टीम आई थी हमारे नगर अध्यक्ष यहां बैठे है। आज वहां पानी की सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं, पानी के लोगों को बिल आ रहे हैं हमारे को हमारे ही पानी के बिल आ रहे है । दूसरी बात जड़ोल बस्ती से एक रोड सलवाणा को जाता है वहां के लिए क्या आप बर्षालय भी बनाएंगें । जहां जंहा	

	पानी के स्त्रोत मिलेगें उनको भी बचाने का क्या आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा । जब अचानक रोड से गाडी गिरेगी तो आसपास के घरो को हमेशा खतरा बना रहेगा । पांच साल के बाद मकान डैमेज होता है उसकी क्षतिपुर्ति कौन देगा । दूसरी बात आई है कि कीमत क्या मिलेगी । आदरणीय जिला दण्डाधिकारी साहब ने जो कीमत फीक्स किया हुआ है, वही मिलेगा । जब कीमत का काम शुरू हुआ जो बंजर भूमि 8 और 10 लाख प्रति विस्वा कीमत पर बिक रही है जो हमारे मकान यहां बने है उसकी भी कीमत उसी के बराबर दी जाए । बुक वैल्यू एकदम बढ जाती है तो उसे यही कीमत मिलेगा या हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 की बुक वैल्यू के हिसाब से मिलेगा । पहले जो नल 4 सौ रूपये का बाजार में मिलता था आज वह बाजार में एक हजार रूपये का मिल रहा है तो 6 सौ रूपया तो जेब से चला गया । मैंने पढा था की कोर्ट की डारैक्सन है की 4 टाईम पेमैंट मिलेगी। इसलिए मै सभी से निवेदन करता हूं कि कीमत लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए बनाए जाएं यही मेरा निवेदन है । लोगो को प्राथमिकता देते हुए ही रोड बनाया जायें उन्हे पर्यावरण से कोई लेना देना नही। और उनका रोजगार का साधन बना रहें।	
11.	**<u>श्री हेम राज पूर्व प्रधान , गांव डगराउ , जिला मण्डी –</u>** सर, वर्ष 1977 में सुन्दरनगर नहर से पानी छोडा गया था । हमने यह नहीं सोचा कि आने वाले समय की समस्या होगी । वहां पर जो पैदल भी चलता है उसे आज काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है । पहले किसी के पास ट्रैक्टर नही होते थे अब तो लोगों के पास ट्रैक्टर भी है इसलिए वे ट्रैक्टर के माध्यम से खेती करना चाहते हैं । और हमारा जो किसान था आज उस समय में जो नहर के उपर फुटब्रिज बनाए गए हैं वह वर्तमान के हिसाब से लोगों के लिए असुविधा	

12.	का कारण बने हुए है । जहां तक कन्ट्रोल रूम की बात है जो पैदल भी चले होते हैं सुन्दरनगर में खरीदनें के लिए, जब वे घर वापिस आते हैं तो उनके पास सामर्थ्य नहीं रहती हैं उनको कन्ट्रोरूम की तरफ से घुमकर जाना पडता है तो उन्हे काफी परेशानी होती थी । जैसे हमारे छोटे किसान है जिनकी जमीन का एक टुकडा रोड से दुसरी तरफ है तो एक टुकडा रोड से इस पार है तो उसके कुछ प्रावधान होना चाहिए। ये सिंचाई भी इस नहर के कारण छिन गई है । उन्हें अपने खेतों तक जाने के लिए जगह–जगह से रास्तों का प्रावधान होना चाहिए और जहां जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जैसे कनैड स्कूल, धनोटू बाजार इत्यादि में सब–वे का प्रावधान होना चाहिए । जब ऐसा होगा तो वहां किसानो को और व्यापारी वर्ग को सुविधा मिलेगी । आजकल कुछ ही दिन बाद गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी इसके लिए मैं चाहूंगा उसके लिए अपने खेतों में आने जाने के लिए इस रोड के बनने पर सब–वे का होना बहुत ही लाजमी होगा ताकि ऐसी गलती न हो।	
12.	**श्री पी0एल0 रावत, गांव भुवाणा–** एक साल पहले फोरलेन के बारे में बात चली थी और कहा गया था कि थोडे ही समय बाद इस पर काम शुरू होने वाला है । जहां पर भी बैठे वहां पर सबके घरो/ दुकानों मे फोर लेन के बारे में ही चर्चा हो रही है। मान्यवर पुगरु में जो हमारी जमीन है मैनें पिछलें साल ही वही पर मकान बनाया था जो पुंजी विदेश मे जाकर कमाई थी वह सारी की सारी वही घर बनानें में लगा दी। यहां पर आयें हुए एक महीना हो गया किसी ने कहा था कि 14 तारिख को मिंटिग है तो किसी ने कहा कि परसों है। सो महेादय जी जो इंजिनियरिंग कॉलेज पुगरु में बना है इसके नीचे जो करव है मै भी पेसे से इंजिनियरिंग हूँ। थोडी सी नॉलेज है साईड से बना दो। क्योकि इसमें तो	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी–** आप यहां हमारे पटवारी से मिल लीजीए शायद वह आपकी समस्या का हल करने में सक्षम हो 1

	120–30 कि0 मी0 की रफतार से गाडी चलेगी । जो फोर लेन बनना चाहिए लेकिन हमें किसी नें नही बताया कि फोर लेन आ रहा है और उसके कारण मैंने अपना कन्सट्रकशन वर्क (construction) भी रोक दिया है कि फोर लेन आ रही है। इसलिए जो पुगरु मे सडक बन रही है उसका कार्य हम रोक देगें इसके लिए कृप्या हमें बताएं कि इस समय हम क्या करें । हमें सारा प्लान प्रोजैक्टर के द्वारा समझाया जायें।	
13.	**श्रीमती रमा देवी, प्रधान ग्राम कनैड, जिला मण्डीः–** मैं अपनी समस्या आपके सामनें रख रही हूॅ बाई पास जो है सुकेती खड्ड से बनना चाहिए। वहां पर जनसंख्या के लिए भी जगह है और वहां पर सरकारी जमीन भी ज्यादा है। हमारे यहां जो भी नौलखा से लेकर डडौर तक जितने भी गांव पडते हैं उन सबको बचाया जाए । वहां से फोरलेन नहीं होनी चाहिए । हमारे जो कनैड के और भौर के लोग हैं उनकी भी यही प्रार्थना है कि सुकेती खडड से होकर फोरलेन बनें । वहां से लोगों को बिजनैस मिल जाएगा और हमारी ग्राम पंचायत कनैड और भौर से भी बना रहेगा । जब फोरलेन बनेगी तो जो भी धार्मिक स्थल हैं वह कहां स्थापित होगे । धार्मिक स्थल तोडेगें तो कहां स्थापित करेगें । आपसे मेरी प्रार्थना है कि सुकेती खडड से होकर बाई पास लें । ताकि हमारें लोंगों को रोजगार मिल सकें। क्या आप वहां से लेकर जाएगें या नहीं इस बात का जबाव दें ।	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी–** इस बात पर हम विचार करेगें । यह दिख रहा है, इस पर मैं विचार जरूर करूंगा । बाकी जो आपका सवाल है धार्मिक स्थलो का इनको सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करेगें । आप लोगों की मद्द से ही हम बदलेंगें, क्या करना है उसमें आपकी ही मदद चाहिए। और जल स्त्रोतो को पूरी तरह बचाया जायेंगा। इसका रिपोर्ट में पुरा प्रावधान है।
14.	**श्रीमती नमिता शर्मा , प्रधान ग्राम पंचायत बरोटी डैहर , जिला मण्डीः–** सर, हमारे पूरे भन्तरेड गांव से जो फोरलेन आ रहा है की भूमि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है । इस जमीन पर फोरलेन आने की वजह से सभी की खेतीवाडी खत्म हो जाएगी । जो कृषि का काम धन्धा है, वह तो पूरी तरह ही खत्म हो जायेंगा।	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी–** जहां तक आपने कृषि योग्य भूमि की बात कही हम कोई पूरी की पूरी भूमि आपकी एक्वायर नही कर रहे हैं । हम 45 मीटर लेगें । रहा सवाल वहां के होटल, ढाबे खोलने का तो जिस सडक

	क्षतिपूर्ति तो आप देगें। लेकिन जिनकी कुछ लोगों की जो छोटी गाडियां है क्या आप उनको रोजगार देगी। जो फोर लेन बनेगा वह हमारी जमीन से काफी उपर आ जायेगा। उसपर आप कुछ ढावा व दुकान बनाकर क्या आप देगें। और हमारें ज्यादातर लोग नेचुरल रिर्सोसीज पर ही निर्भर है कृप्या उन्हें बचाकर रखीयें। जहां से फोरलेन का सर्वे हुआ है वहां से इस बी0 एड0 कॉलेज को 10 फुट साइड को छोडकर फोरलेन को उसके साइड से बनाया जाए नहीं तो वहां पर बी0 एड0 के लिए समस्या पैदा होगी । और जो विद्यार्थी है अगर उन्हे भी अगर आर पार जाना है 4–5 कि0 मी0 ज्यादा चलना पडेगा। इसमें कुछ न कुछ प्रावधान किया जायें।	पर गाडी 180–190 की तेज रफ्तार से चलेगी । वहां होटल और डाबों का ज्यादा औचित्य नहीं रह जाता है । हां, 20–25 किलामीटर के बाद सड़क के किनारें में यह प्रावधान रखा गया है । जैसे कि हमारें एक भाई साहिव ने बताया कि 90–100 किलामीटर की स्पीड से जब गाडी आएगी दुर्घटनाएं होने के आसार रहेगें । बाकी जहां तक रोजगार देने का सवाल है हमारी कम्पनी यहां 20–25 साल रहेगी । यहां जो भी सकिल (Skill) ऐविलेवल (Available) है, उन्हे उसी के अनसुार रोजगार दिया जा सकता । बाकी ढाबे वगैरह हर जगह नहीं खेाल पाएंगें ।
15	**श्री एन0 एस0 चौधरी, गांव ढढौर, जिला मण्डी –** सर, यहां कहा गया है कि बाई पास सुकेती खड्ड से लिया जाए हम इससे प्रभावित करते हैं । जो डडौर में स्थापित सडक है उससे ज्यादा उंच्चाई नहीं जानी चाहिए । क्योंकि 1960 में भी वहां अत्यधिक फलड़ आया था तो उससे वहां के पर्यावरण में फर्क पडा था और उसमें भी बहुत कैजुअज्टी पाई गई थी। और इसकी उच्चाई न बढाई जायें। और आपनें अगर यहां पर फलाई ओवर न बनाया तो नेरचौक को बचानें की बजह से आप इस सबको खत्म की देगें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे गौर किया जाए ।	
16	**श्री जितेन्द्र वर्मा , एन0 जी0 ओ0 लीडर, गांव नौलखा जिला मण्डी** – बहुत सारी बातें लोगो ने टच कर लिया है लेकिन पर्यावरण के उपर किसी ने कुछ नही कहा जो मिट्टी इस रोड से निकलेगी उस मिट्टी को ट्रको	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी–** मिट्टी के लिए हमारी डी0 पी0 आर0 में प्रावधान है। उसको विल्कुल इम्पलीमैंट किया जायेंगा। अगर कमेटी

	द्वारा उठाया जायेंगा और मिट्टी 100–200 मी0 के दायरे में सडक के चारों तरफ गिरेगी। जिसमें कि लोग अपने कपडे सुखने नही डाल सकते, लोगों को सांस लेने में समस्या होगी। इसलिए वहां पर कम्पनी और प्रोजैक्ट के लोगों को वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। दूसरे यह कि जब कम्पनी आती है तो कमेटी फोरम की जाती है । यदि कम्पनी अपने मनमाने तरीके से कार्य करने लगती है तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी एक सशक्त कमेटी फोरम हुई हो जिसमें प्रशासन के लोग भी हो । और अन्य भी ऐसी कमेटी का गठन सबसे पहले किया जाए ।	बन जायेंगी तो मैं स्वागत करता हूँ। जिसकी जो भी समस्या होगी वह, वहां पर रिपोर्ट करें। क्योंकि यह प्रोजैक्ट तभी सफल होगा जब हम दोनों मिलकर चलेंगे। कमेटी का फार्म होना सही है तभी यह प्रोजैक्ट सफल होगा अदरवाईज बिल्कुल नहीं ।
17	**श्री प्रेम ठाकुर, एडवोकेट, सुन्दरनगर कोर्ट–** मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मै वर्मा जी की बात पर दो प्वांइट और जोडना चाहुगा। जो पानी की समस्या है वी0 एस0 एल0 प्रोजैक्ट ने हमारा 30–35 प्रतिशत पानी हमसे छिन लिया गया है मैने सुना है कि सुन्दरनगर के लिए दो हाइवे टनल भी है हाई प्रोफाइल टनल है लेकिन मुझे पता नही है कि प्रोपोजल में क्या है। लेकिन टनल की बजह से पानी की समस्या गंम्भीर होनें जा रही है। क्योकि जिस क्षेत्र में यह टनल बनेगी उस क्षेत्र में पानी की भारी समस्या हैं। जडोल में पानी है उस पानी को बचानें के लिए पहले से ही उसका अलटरनेट लोगों को बता दिया जायें जब एन0 एच0 बनेगा उसमें बहुत ज्यादा मजदूर आयेगें, हैवी मशीनरी कई तरह की और दूसरी चीजें यहां कार्य करनें के लिए आयेंगी । जिससे पर्यावरण पूरी तरह खराब हो जाएगा । और मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण को बचानें के लिए यहां पर तेजी से कार्य किया जायें। और लोगों में जागरुकता पैदा कि जायें। जो आपका ट्रैक होगा उसको घोषित किया जायें ताकि लोगों में भ्रान्ति न रहें। जैसे इन्जीनियर साहिव ने अपनें मकान का काम रोक दिया हैं मैं चाहता हूं कि जो कार्यकारिणी अधिकारी है वह इसमें काम करें। जैसे	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी–** मजदूरो के लिए अलग से एक आशियाना बनाएगें और 20–25 साल तक उनकी मशीनरी तथा मजदूर को जगह जगह पर बसाएंगें ताकि लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके । यह प्रोजैक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो क्योंकि यह बी0 ओ0 टी0 वेसड प्रोजैक्ट है इनका 3 साल का प्रोजैक्ट है और इन्हें यहां पर 25 साल और रहना हैं। अगर यह 3–5 साल लगाते है तो इनका का कन्सैशन पीरियड (concession period) कम हो जायेंगा। उससे आप निश्चिन्त रहिए अगर लेट करेगें तो उनका ही नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं हैं । यह सब सम्भव है ।

	मैडम को लग रहा है कि पूरा का पूरा गांव उजड़ जायेंगा। ऐसी बात नही है इसके लिए आपको सही कदम उठाने होगें ।	
18	**श्री काका राम, गांव भौर, जिला मण्डी –** सर, फोरलेन बनने से लोगों को कोई नुकसान नही होगी फोरलेन बनना चाहिए बहुत ज्यादा सुविधाएं होगी । बीमार आदमी को बडे अस्पतालों में ले जाने के लिए तुरन्त सुविधा रहेगी । मेरा निवेदन है खासकर क्रसिंग ठीक तरह से रखे जाए । जैसे स्कूल है जिन लोगों की जमीनें दूसरी तरफ सडक से होगी उनको कासिंग के लिए खास ध्यान रखा जाए और इसका नक्शा तैयार किया जाए बाद में इसका कोई आपति नहीं है।	
19.	**श्री राजेन्द्र झावे चौमुखा, जिला मण्डी–** सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमारे पास पहले कम्पनी के लोग आएं और हमारी समस्या सुने । जो फोरलेन का सर्वे हुआ उसमें हमारी भी जमीन आती है परन्तु जमावन्दी की नकल हमारे नाम नहीं हैं । इसके लिए क्या करें । दूसरा मेरा प्रश्न है हमारे बुजुर्गो के नामों में जमाबन्दी में बहुत गडवड है । मेरी माता और मेरे भाई का नाम वैसे कुछ और है और जमाबन्दी में कुछ और है । तो इसके बारे में परिवर्तन के लिए बहुत लम्बी प्रकिया है । पहले अखबार में नाम देना पडेगा और भी इसमें लम्बी और खर्चीली प्रक्रिया है । तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जब क्षतिपूर्ति मिलेगा तब उनकों उनके गलत नाम से सम्बधित राहत देने के लिए आवश्यक पग उठाएं ताकि क्षतिपुर्ति मिलने में किसी परेशानी का सामना न करना पडे। तीसरे आने वाले समय में हमें जो भी क्षतिपुर्ति हमें कुछ भी मिलेगा उसके बाद भी हमें एक लम्बी लडाई सरकार से और कम्पनी से लडनी पडेगी इसलिए एक युनियन हम सबको बनानी ही पडेगी ।	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी–** इसमें सेक्सन 3 (A) के तहत अधिसुचना होगी कौन कौन से खसरा नम्बर आ रहे हैं, यह पता लैड एक्युजिसन के ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं कि कहां कितनी भूमि इनवोल्व हो रही है । नाम बदलनें के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको जिला प्रशासन की ही मदद लेनी पडेगी । जहां नाम बदलनें की बात है उसमें हमारा प्रोजैक्ट कुछ भी मदद नही कर सकता। तीसरी आप की बात युनियन की है तो यह आपका निजी मामला है।
20	**श्री मुनी लाल , ग्राम पंचायत भंगरोटू** – मैं दो –चार	**परियोजना निदेशक श्री कौल जी:–**

	बातें करना चाहता हूँ मेरा यह प्रश्न है कि ढढौर से लेकर नागचला तक की भूमि बहुत उपजाऊ है । उसके बारे में बहुत ध्यान रखना पडेगा ताकि वह भूमि वर्वाद न हो । फोरलेन बननी चाहिए इसका हम समर्थन करते हैं लेकिन उसमें इस तरह की जो हमारी उपजाऊ भूमि है उस भूमि का किसानों को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि भविष्य में भी हमने उस जमीन के लिए ट्रैक्टर उतारना हो तो उसमें प्रावधान रखा जाए । जैसे मेरे खेत है एक या दो बिस्वा के अगर वह रोड पर चले जाते है और उसमें कुछ जमीन बच जाती है तो ऐसा न हो कि जो बची हुई भुमि दूसरे किनारे पर एक विस्वा या दो विस्वा है उसको भी आप लें लें। फोर लेन के नजदीक जितनें भी लोग रहते है उन्हे रोजगार उपलब्ध करबाया जायें। उसमें ऐसा नही की बाहर के मजदूरो को यहां लाया जायें और यहां के मजदुरों को कोई न पुछे। बहुत से गरीब आदमी है उन्हे रोजगार मिलना चाहिए।	यह जो हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग है के लिए अधिनियम 1956 बना हुआ है उसके अनुसार जितना ज्यदा लाभ होगा हम प्रभावितों को दे सकते हैं वह हम पूरे का पूरा देगें । रोजगार के सवाल पर भी मैं आपको बता चुका हूं जितना भी होगा इसके लिए हमारे पास यहां स्कील (Skill) एवीलेवल (Available) होगा उनके अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा । जहां तक रोड की उंच्चाई के बारे में सवाल है वह हम उच्च मार्ग के डीजाईन को देखकर ही कुछ बता सकते हैं ।
21	**<u>श्री विष्णु लाल वर्मा, ग्राम पंचायत जडोल–</u>** मैं यह कहना चाह रहा था कि जब सर्वे हुआ था तो फोरलेन का लगभग एक साल पहले जडोल से पुंग तक तो उसमें हमारी सडक आ रही थी । बाद में यह सर्वे वहां से नहीं हुआ, उसे बदला गया इसका क्या कारण है।	**<u>परियोजना निदेशक श्री कौल जी–</u>** वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत से गांव उजड़ रहे थें । पूरे का पूरा एरिया बाहर का आ रहा था और उपर से बिजली की एच0 टी0 लाईन गुजर रही थी जिसको बदलना आसान नही था । इसलिए हमने यह सर्वे बदला । नही तो पूरे के पूरे पहाड़ उपर से आ जानें थे। पूरा का पूरा गॉव उजड़ रहा था। एच0 टी0 लाईन उपर से जा रही थी इसे बदलना मुश्किल था। इसलिए हमनें यहां से इसको बदला।

श्री डी० के० रतन, अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी, मण्डी– आप सबने अपने–अपने विचार रखे उन बहूमूल्य विचारों के लिए मैं आपका तहे–दिल से स्वागत करता हूं और एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि हमें यह सडक चाहिए और हम इसका स्वागत करते हैं, यह आप सब लोगों ने अपने विचारों में व्यक्त किया । आपके सुझाव बहुत अच्छे थे, आप चाहते हैं कि सडक बननी चाहिए, यह विकास के लिए एक सराहनीय कदम है । जिस तरीके से आपनें अपनें विचार रखें मै उससे बहुत खुश हुं। आपके सुझाव बढे अच्छे थें कि सडक बननी चाहिए। मै आप सबकी ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार से अनुरोध करना चाहुँगा की अगर आपको लगता है कि जो लोगो ने अपनें सुझाव तथा आपतियां दर्ज करवा रखी है उन पर ये अपनी डीसकियेशन्स लगा सकते हैं तो उस पर जरुर लगायें तथा हमारें प्रभावित लोगो को जितना फायदा पहुचा सकते हैं, उतना पहुँचाएं। सबने कहा की रोड का कार्य जल्द हो जाना चाहिए। लोगो को क्षतिपुर्ति (compensation) जरुर मिलनी चाहिए, तथा सबको पूरी–पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनका कितना क्षेत्र जा रहा है, कितनें घर जाऐंगे, इसमें लोग पादर्शिता चाहते है। फोरलेन के निर्माण कार्य में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड न हो । मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन की तरफ से आपको पूरा सहयोग देगें और जो लोगों की आपत्तियां हैं उनकों सुलझाने में भी सहयोग करेंगें ।

अंत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परियोजना निर्देशक ने उपस्थित जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में सहयोग मांगा तथा क्षेत्र के विकास में यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा जनता का आभार व्यक्त किया । जन–सुनवाई के समापन से पूर्व कार्यवाही के सार को अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी जिला मण्डी (हि.प्र.) द्वारा उपस्थित लोगों के समक्ष बताया गया। तत्पश्चात इसका विवरण रिकार्ड किया गया । अन्त में अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी मण्डी व सहायक अभियन्ता पर्यावरण बोर्ड बिलासपुर द्वारा लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी
जिला मण्डी (हि.प्र.)